देय शुल्क के प्रकार

- **गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क-**गैर-आरक्षित श्रेणी (ओपन श्रेणी) के लिए आवेदन के समय देय गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित) निम्नानुसार है:

नियमित आरओ के लिए	Rs. 10,000/-
ग्रामीण आरओ के लिए	Rs. 8000/-

- **गैर-वापसी योग्य निश्चित शुल्क / बोली राशि**-डीलर के स्वामित्व वाली साइटों के मामले में, ओएमसी से एनओसी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर गैर-वापसी योग्य निश्चित शुल्क (जीएसटी सहित) देय होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है

नियमित आरओ के लिए	Rs. 15 lakhs
ग्रामीण आरओ के लिए	Rs. 5 lakhs

- निगम के स्वामित्व वाली साइटों (सीएफएस के अलावा) के मामले में आवंटन के लिए बोली लगाना शामिल है, बोली राशि (जीएसटी सहित) होगी:

नियमित आरओ के लिए	Rs. 30 lakhs
ग्रामीण आरओ के लिए	Rs. 10 lakhs

- **लाइसेंस शुल्क-** लाइसेंस शुल्क डीलर द्वारा समय-समय पर लागू प्रति केएल (किलो लीटर) के आधार पर देय होगा।
- **सुरक्षा जमा (एसडी) / प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी)**-लॉट/बोली खुलने के बाद, अनंतिम रूप से चयनित पीएसीएस को 10 दिनों के भीतर कुल सुरक्षा जमा (एसडी) राशि का 10% जमा (आईएसडी) जमा करना आवश्यक है। ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा (एसडी) इस प्रकार है:

नियमित आरओ- खुली श्रेणी - 5 लाख रुपये
ग्रामीण आरओ- खुली श्रेणी - 4 लाख रुपये

अनंतिम रूप से चयनित पैक्स द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

- सक्षम प्राधिकारी से पैक्स के पंजीकरण प्रमाणपत्र / निगमन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
- आवेदक द्वारा परिशिष्ट-XB के अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र (OMC का ब्रोशर देखें)
- स्वामित्व / पट्टा अधिकारों के समर्थन में भूमि दस्तावेजों की प्रति (प्रस्तावित भूमि का खसरा / खतौनी / गुट / सर्वेक्षण संख्या / समझौते आदि)
- प्रस्तावित भूमि का स्केच / साइट मैप आयाम के साथ.
- परिशिष्ट - III (भूमि के प्रस्ताव के लिए सहमति) यदि लागू हो
- आवेदन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकरण पत्र और संकल्प की प्रति
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र

अस्वीकरण

नोट: यह दस्तावेज़ केवल एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। कृपया पूर्ण विवरण और विस्तृत आवेदन प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक ओएमसी संचार और "नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर (जून 2023)" देखें.

वैबसाइट:
https://www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/viewads

ब्रोशर लिंक :
https://www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/assets/pdfs/

स्लोत:petrolpumpdealerchayan

हमसे संपर्क करें

पता:
सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक), बर्ड, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226 012, भारत
फोन: +91-522-2421799 (सी-पेक)
ई-मेल: cpec.bird@nabard.org

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के लिए पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप

IndianOil Bharat Petroleum HP

सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक), बर्ड, लखनऊ द्वारा संकलित

BIRD

पृष्ठभूमि

भारत में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सहकारिता मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत पैक्स को नई पेट्रोल और डीजल डीलरशिप के लिए प्राथमिकता दी गई है और उन्हें थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट्स में बदलने की अनुमति दी गई है। इसके जवाब में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के लिए नियमित और ग्रामीण खुदरा आउटलेट्स के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) के तहत पैक्स को आरक्षण दिया गया है।प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को पेट्रोल और डीजल डीलरशिप प्रदान करने के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

- ग्रामीण सहकारी समितियों को सशक्त बनाना
- पैक्स के लिए नए आय के अवसर
- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना
- सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना
- ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना

स्थान

रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान संबंधित तेल कंपनी (ओएमसी) द्वारा वाणिज्यिक / न्यूनतम मात्रा विचारों (विज्ञापन का संदर्भ लेने के लिए पैक्स) के आधार पर की जाती है, जो निम्नलिखीत हो सकते है :

* **नियमित रिटेल आउटलेट(आरओ) :** राजमार्गों और शहरी / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित (किसी शहर / कस्बे की नगरपालिका सीमा के भीतर)।
* **ग्रामीण रिटेल आउटलेट (आरओ)** : ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, लेकिन राजमार्गों पर नहीं (किसी शहर / कस्बे की नगरपालिका सीमा के बाहर)

पैक्स के लिए पात्रता आवश्यकताएँ

पैक्स केवल 'ओपन' श्रेणी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल डीलरशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके लिए, उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

1. **पंजीकरण**: पैक्स का भारत में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912, या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत पंजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन की तारीख से कम से कम 3 वर्ष पूर्व पैक्स का गठन या पंजीकरण किया गया होना चाहिए।

2. **भूमि स्वामित्व**: भूमि की उपलब्धता के आधार पर पैक्स को तीन समूहों में विभाजित किया गया है:

- समूह 1: पैक्स के पास विज्ञापित स्थान पर भूमि का स्वामित्व है या कम से कम 19 वर्ष 11 महीने के लिए दीर्घकालिक पट्टा (लीज) है।
- समूह 2: पैक्स के पास उपयुक्त भूमि की खरीद या दीर्घकालिक पट्टे (कम से कम 19 वर्ष 11 महीने) के लिए 'फर्म ऑफर' है।
- समूह 3: पैक्स के पास कोई भूमि नहीं है, जो केवल SC/ST श्रेणी के स्थानों के लिए लागू है।

3. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: पैक्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता यह लिखित प्रमाण देगा कि वे डीलरशिप संचालन के लिए संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

तेल कंपनियों द्वारा रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए समाचार पत्रों या वेबसाइट (www.petrolpumpdealerchayan.in) पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

पेट्रोल/डीजल पंप रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।

आवेदन जमा होने के बाद, ओएमसी आवेदन और प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और तदनुसार आगे बढ़ेगी।

चयन प्रक्रिया

चयन लॉटरी ड्रा या बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो खुदरा आउटलेट साइट के प्रकार पर निर्भर करेगा। कॉर्पस फंड योजना के तहत कंपनी के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट्स और डीलर स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट्स के लिए पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा।

बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन कंपनी के स्वामित्व वाले डीलर संचालित साइटों के लिए किया जाएगा, सिवाय उपरोक्त कॉर्पस फंड स्थानों के।

हालांकि, यदि बोली राशि में टाई होता है, तो अंतिम चयन टाई बोली लगाने वालों के बीच लॉटरी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा

उपभोक्ता पेट्रोल पंपों (सीपी) को खुदरा दुकानों में परिवर्तित करना

मौजूदा पैक्स उपभोक्ता पेट्रोल पंप (सीपी) को आवश्यक दस्तावेजों और स्वीकृति हलफनामे के साथ एक ऑनलाइन आवेदन पत्र (प्रारूप- परिशिष्ट- IB) जमा करके खुदरा में परिवर्तित होने का विकल्प चुनना चाहिए, जो कि नामित ओएमसी कार्यालय (खुदरा प्रभागीय कार्यालय (IOC), क्षेत्रीय कार्यालय (HPC), क्षेत्रीय कार्यालय (BPC) में लागू हो।